उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देशों के लिये टाइम्स रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के अच्छे प्रदर्शन से उम्मीद जगती है।

हमें अच्छे शोधकर्त्ताओं को प्रतिष्ठाजनक स्थान देना होगा।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

अगले कुछ महिनों में विश्वविद्यालयों की कई विश्वस्तरीय एवं राष्ट्रीय रैंकिंगों की घोषणा होनी है। इस की शुरूआत टाइम्स हायर ऐजूकेशन (टीएचई), लंदन ने वर्ष 2020 के लिये अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर के कर दी है। इस विशिष्ट रैंकिंग में भारत के 11 विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सांइस, बंगलुरू को 16वां स्थान मिला है।

ध्यान रहे कि यह टाइम्स हायर एजूकेशन की मूल विश्वस्तरीय रैंकिंग नहीं है। टीएचई की मूल रैंकिंग 2004 में क्यू एस कंपनी के साथ शुरू की गई थी। दुनिया भर के विद्यार्थी और शिक्षक जिन यूनिवर्सिटी रैंकिंगों का उपयोग करते है, उन में टाइम्स हायर एजूकेशन, एआरडब्ल्यू यू और क्यू एस सर्वोपरि मानी जाती है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले विश्वविद्यालयों की रैंकिंग वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। शुरूआत के समय इस का नाम ब्रिक्स एवं उभरती अर्थव्यवस्था वाली रैंकिंग था। इस रैंकिंग में चीन, भारत, रूस, ब्राजील, ताईवान, टर्की और दक्षिण अफ्रीका जैसे 47 देशो के विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है। इन देशों को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) की एफटीएसई की सूची के आधार पर चुना जाता है।

उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के विश्वविद्यालयों की टाइम्स हायर एजूकेशन द्वारा वर्ष 2020 के लिये घोषित रैंकिंग में ब्रिक्स देशों के 533 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग सूची में भारत के 55 विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। आईआईटी, खड़गपुर और आईआईटी, बंबई को क्रमशः 32वीं और 34वीं रैंक मिली है। इन संस्थानों के अलावा कुछ और भारतीय संस्थान शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल हैं। इनमें आईआईटी, दिल्ली 38वें स्थान पर, आईआईटी, रूड़की 58वें स्थान पर ओर आईआईटी, इंदौर 61वें स्थान पर आये है। दो अन्य भारतीय

संस्थान, आईआईटी, मद्रास तथा आईआईटी, रोपड़ 63वें स्थान पर हैं। इस तरह कुल 11 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है।

टाइम्स हायर एजूकेशन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के 533 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के 56 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस सूची में चीन के विश्वविद्यालयों का प्रभुत्व देखा गया है। इस रैंकिंग के श्रेष्ठतम 10 विश्वविद्यालयों में 7 चीन से हैं।

टाइम्स हायर एजूकेशन द्वारा हर वर्ष जारी की जाने वाली विश्वविद्यालयों की विश्वस्तरीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते किन्तु उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के विश्वविद्यालयों की वर्ष 2020 की सूची में चीन के बाद भारत की प्रमुखता होना एक उत्साहवर्धक समाचार ही कहा जायेगा। इस रैंकिंग में शामिल 47 देशों के विश्वविद्यालयों से टक्कर लेना आसान नहीं। रैंकिंग एजेंसी टीएचई भी भारतीय विश्वविद्यालयों के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित दिखाई देती है। टीएचई के सीईओ फिल बैटी का कहना कि भारत के कुछ विश्वविद्यालयों ने निस्संदेह अच्छी प्रगति दिखाई है। ये भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिये एक नया मोड़ हो सकता है। फिल बैटी का कहना है कि इस उत्साह जनक प्रदर्शन का आंशिक श्रेय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में घोषित 'इन्स्टीट्यूट ऑफ ऐमीनेंस' योजना को दिया जा सकता है।

भारतीय उच्च शिक्षा की विश्वस्तर पर चिंताजनक स्थिति से उबारने के कई प्रयास पिछले वर्षों में किये गये हैं। इनमें एक प्रमुख प्रयास था मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई एनआईआरएफ रैंकिंग, जो कि विश्वस्तरीय तो नहीं है किन्तु इसे शुरू करने का प्रमुख मकसद भारतीय विश्वविद्यालयों को कुंभकर्णी निद्रा से जगा कर उन्हें रैंकिंग संस्कृति और विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिये तैयार करना था।

कई शिक्षाविद रैंकिंग की अंधी दौड़ से खुश नहीं होते। वे अक्सर यह प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों के लिये राष्ट्रीय और विश्वस्तरीय रैंकिंगो में भाग लेना क्यों जरूरी है? ऐसा करने से उन्हें क्या मिलेगा? अगर गहराई से देखें तो मालुम पड़ेगा कि विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहे विद्यार्थियो के आव्रजन का निर्णायक घटक मुख्यतया रैंकिंग होता है। पिछले 30 वर्षो में दुनिया ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की और तेजी से बढ़ी है। यूएसए, यूके, यूरोप, कनाडा और

आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा विदेशी विद्यार्थियो की फीस और उनके रहने–सहने के खर्चों से आता है। रैंकिगों की लोकप्रियता का दूसरा प्रमुख कारण है दुनिया भर से अत्यधिक प्रबुद्ध, रचनात्मक और शोध प्रतिभाओं को अपने–अपने देशों में आकर्षित करना। कहा जाता है कि 21वीं सदी में पूंजी और श्रम के लिये विश्वयुद्ध नही होंगे किन्तु मानवीय प्रतिभा के लिये सभी देश मारामारी करेंगें। यही कारण है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले तमाम देशों की सरकारें और उन देशों के विश्वविद्यालय पिछले एक दशक से अपनी रैंकिंग सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

भारत की उच्चशिक्षा में हर स्तर पर एक सवाल बार–बार उठता है कि विश्व स्तरीय रैंकिगों में हमारे विश्वविद्यालय क्यों पिछड़ जाते हैं? आईआईटी, आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय संसाधनों कमी नही रहती किन्तु वे भी इन रैंकिगों में आखिर अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते?

विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा रैंकिंगो में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग शिक्षण, अनुसंधान, उद्योगों से होने वाली आय और अन्तर्राष्ट्रीयकरण के प्रमुख आधारों पर की जाती है। टाइम्स रैकिंग में 30 प्रतिशत जोर शिक्षण की गुणवत्ता पर, 60 प्रतिशत जोर अनुसंधान और साइटेशन पर, उद्योगों से आय पर 2.5 प्रतिशत और अन्तर्राष्ट्रीयकरण पर 7.5 प्रतिशत जोर दिया जाता है। 2020 की की विश्वस्तरीय टाइम्स रैंकिंग का विश्लेषण करने पर मालुम पड़ता है कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थान पढ़ाई लिखाई और उद्योगों से जुड़ाव के मामले में तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं किन्तु अनुसंधान के क्षेत्र में मात खा जाते है। एक ओर भारतीय प्रोफेसरों में शोधपत्र प्रकाशित करने की उद्यमिता और उत्साह कम है तो दूसरी ओर उनके शोधपत्रों का साइटेशन इम्पेक्ट भी अपेक्षाकृत कम पाया जाता है।

अगर हम विश्वस्तरीय रैंकिगों में भारतीय यूनिवर्सिटियों के खराब प्रदर्शन के बारे में शिक्षकों की राय जानने की कोशिश करें तो अनेक शिकायतें सुनने की मिलेंगी, यथा–विश्वविद्यालयों की लेबोरेटरियों और लायब्रेरियों में रिसर्च संसाधनों की कमी होना, टीचिंग और प्रशासनिक कार्यों का बोझा ज्यादा होना, कालेजों और विश्वविद्यालयों में पिछले कई दशको से शोध कार्यो की हो रही उपेक्षा। उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में यूएसए और यूरोप के विश्वविद्यालयों के खुलेपन और वैचारिक अभिव्यक्ति की छूट देना एक प्रमुख प्रेरक तत्व रहा है। भारतीय विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते

हुए दबाव और राजनीतिकरण ने शोध और अनुसंधान के माहोल पर विपरीत असर डाला है।

विश्वस्तरीय रैंकिगों में भारतीय विश्वविद्यालयों की दुर्दशा पर दुखी और निराश होने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें भारत को उच्च शिक्षा का आकर्षण केन्द्र बना कर लाखों विदेशी विद्यार्थियों को भारत में पढ़ने के लिये आकर्षित करना है तो केन्द्र व राज्य सरकारों को मिलजुल कर उच्च शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। उच्च शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय आय का 1 से 1.5 प्रतिशत खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इसे अगले तीन वर्षों के भीतर 2.5 प्रतिशत करना होगा। अभी हाल में डा. कस्तूरीरंगन कमेटी ने नई शिक्षा नीति के प्रस्तावित मसौदे में शोध व अनुसंधान पर रू. 20,000 करोड़ की वार्षिक राशि खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। यह स्वागत योग्य कदम होगा किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह धनराशि भी पर्याप्त नहीं है।

भविष्य में विश्वस्तरीय रैंकिंगों में हमारा मुकाबला यूएसए, यूके और जर्मनी के साथ–साथ चीन, जापान, सिंगापुर और हांगकांग से भी होगा। हमें अच्छे यूनिवर्सिटी शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को प्रतिष्ठाजनक स्थान देना होगा और देखना होगा कि वे देश में ही रह कर शिक्षण, शोध एवं अनुसंधान करें। देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों के छात्रों की फीस, छात्रवृत्ति और होस्टल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो भी शिकायते हैं उन्हें दूर करने के लिये यूनिवर्सिटी कैम्पसों के रख रखाव पर समुचित ध्यान देने की जरूरत होगी। हमारे देश में पब्लिक यूनिवर्सिटियों की अपनी महत्ता रही है, क्योंकि समाज के हर तबके के विद्यार्थी यहां पढ़ाई लिखाई करने के लिये प्रवेश ले पाते हैं। देश के कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करते रहे हैं। क्या उन विश्वविद्यालयों को अगले कुछ वर्षों में विश्वस्तर पर अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिये विशेष वित्तीय सहायता और अधिक स्वायत्तता दी जा सकती है?